....'किसी' को 'उजाड़ा' नहीं बल्कि 'बसाया' जा रहा : ईओ

न खाते में पैसा और न गोदामों में खाद, आखिर कहां गया आरकेवीवाई का करोड़ों, 97 में से एक भी समिति के खाते में योजना का पांच लाख नहीं, किसी के खाते में एक हजार तो किसी में दो हजार

कार्यालय नगर पंचायत बनकटी, बस्ती।

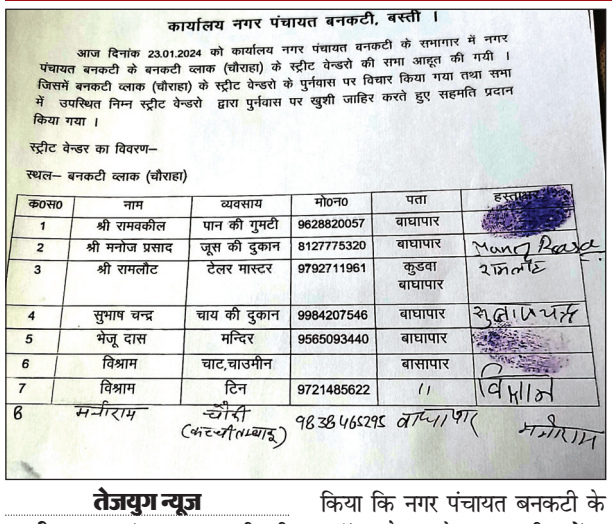

आज दिनांक 23.01.2024 को कार्यालय नगर पंचायत बनकटी के सभागार में नगर पंचायत बनकटी के बनकटी ब्लाक (चौराहा) के स्ट्रीट वेन्डरो की सभा आहूत की गयी। जिसमें बनकटी ब्लाक (चौराहा) के स्ट्रीट वेन्डरो के पुर्नवास पर विचार किया गया तथा सभा में उपस्थित निम्न स्ट्रीट वेन्डरो द्वारा पुर्नवास पर खुशी जाहिर करते हुए सहमति प्रदान किया गया।

स्ट्रीट वेन्डर का विवरण–

स्थल– बनकटी ब्लाक (चौराहा)

क्र0स0	नाम	व्यवसाय	मो0न0	पता	हस्ताक्षर
1	श्री रामवकील	पान की गुमटी	9628820057	बाघापार	
2	श्री मनोज प्रसाद	जूस की दुकान	8127775320	बाघापार	Manoj Prasad
3	श्री रामलौट	टेलर मास्टर	9792711961	कुडवा बाघापार	रामलौट
4	सुभाष चन्द्र	चाय की दुकान	9984207546	बाघापार	सुभाष चन्द्र
5	भेजू दास	मन्दिर	9565093440	बाघापार	
6	विश्राम	चाट,चाउमीन		बासापार	
7	विश्राम	टिन	9721485622	〃	विश्राम
8	मनीराम	चौकी (कच्ची तम्बाकू)	9838465295	बाघापार	मनीराम

तेजयुग न्यूज़

बस्ती।...नगर पंचायत बनकटी की अधिशाषी अधिकारी 'रिचा' ने स्पष्ट किया कि नगर पंचायत बनकटी के ब्लॉक चैराहा के पास स्टीट वेंडर पुर्नवास योजना के तहत उनके लिए प्लेट फार्म का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि वह अपना कारोबार सही तरीके से और सुरक्षित स्थान पर कर सके। बताया कि किसी को वहां से उजाड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उनका पुर्नवास किया जा रहा है।

कहा कि स्टीट वेंडरों की सहमति के बाद ही प्लेट फार्म का निर्माण करवाया जा रहा है। ईओ ने उन लोगों को यह बताना चाहा कि जो यह प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, कि नगर पंचायत चाय वाले, पान वाले, धोबी वाले की दुकानों को उजाड़कर उनका रोजी रोटी छीन कर वहां पर दुकान बनवा कर कब्जा करना चाहती है। यह सही है, कि जिस स्थान पर प्लेट फार्म बनाया जा रहा है, वह जमीन पीडब्लूडी की है, लेकिन पीडब्लूडी की सहमति के बाद ही निर्माण कराया जा रहा है। बताया कि तीन मीटर का लगभग 15 दुकानों के लिए प्लेट फार्म बनाया जा रहा है, और सबसे पहले उन नौ लोगों के नाम एलाट होगा, जिन लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया।

प्लेट फार्म निर्माण करने से पहले ईओ की अध्यक्षता में 23 जनवरी 24 को रामवकील पान की गुमटी, मनोज प्रसाद जूस की दुकान, रामलौट टेलर मास्टर, सुभाष चंद्र चाय की दुकान, भेजू दास मंदिर, विश्राम चाट/चाउमीन, विश्राम टिन एवं मनिराम चैकी कच्ची तम्बाकू के साथ बैठक हुई। इन सभी को विश्वास दिलाने के बाद कि जिस स्थान पर उनका प्रतिष्ठान हैं, उसी स्थान पर उन्हें पक्का प्लेट फार्म दिया जाएगा। तब जाकर इन लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। बताया कि नगर पंचायत बनकटी जिले की पहली नगर पंचायत बन गई, जो स्टीट वेंडरों के पुर्नवास के लिए पक्का प्लेट फार्म बनाकर दे रहा है।

ईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी से भी एक रुपया किराया नहीं लिया जाएगा, बल्कि उन्हें यह प्लेट फार्म निःशुल्क दिया जा रहा है, यह भी बताया कि इन लोगों की सुविधा के एक षौचालय का निर्माण होगा, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ लगाए जाएगें, रोशनी के लिए स्टीट लाइट लगवाई जाएगी और' आई लव बनकटी नगर पंचायत' की सेल्फी प्वाइंट बनाई जाएगी। ईओ ने नगर पंचायत क्षेत्र के लोगों से नगर पंचायत को माडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। क्यों कि बिना जनता के सहयोग से नगर पंचायत विकास नहीं कर सकता।

▸▸ रामवकील, मनोज, रामलौट, सुभाष, भेजू दास, विश्राम और मनिराम की सहमति पर उनका पुर्नवास हो रहा ▸▸ इनके किसी की पान की गुमटी, जूस की दुकान, टेलरिगं, चाय, मंदिर, चाट की दुकान ▸▸ इन लोगों को स्टीट वेडर पुर्नवास योजना के तहत तीन मीटर का पक्का प्लेटफार्म बना कर दिया जाएगा ▸▸ स्टीट लाइट, शौचालय, आरओ और आई लव बनकटी का सेल्फी प्वाइंट की सुविधा मिलेगी ▸▸ पीडब्लूडी की सहमति के बाद स्टीट वेंडरों को पुर्नवास किया जा रहा

...'कब्जा' किया, 'दुकान' बनाया, 'किराए' पर 'दिया'

बनकटी ब्लॉक की दीवार के पीछे पीडब्लूडी की जमीन पर 'पवन चौहान' ने किया दुकानों का अवैध निर्माण, नोटिस देने जा रही पीडब्लूडी

तेजयुग न्यूज़

बस्ती।...बनकटी ब्लॉक क्षेत्र और नगर पंचायत बनकटी के आसपास सरकारी जमीनों पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि उस पर दुकान बनवाकर उसे किराए पर दे दिया। इस क्षेत्र में निरंतर पीडब्लूडी और नगर पंचायत की जमीनों पर कब्जा करने की शिकायतें बराबर आ रही है। इसका फायदा उठाने में वर्तमान और पूर्व सभासद भी पीछे नहीं हैं। नगर पंचायत के ईओ नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, जमीनों पर से कब्जा हटाने के लिए एसडीएम को भी लिख रहे हैं, मगर न तो पीडब्लूडी और न तहसील प्रशासन कब्जेदारों को बेदखल करवा पा रहा है। जिसके चलते सरकारी जमीनों पर निरंतर कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही है। यह किसी से छिपी नहीं है, कि कब्जा करने और कराने के मामले में सत्ता पक्ष के लोग बराबर हिस्सेदार रहें हैं।

कहा भी जाता है, कि जमीन कब्जा करने के मामले में सरकारें किसी के लिए बाधक नहीं बन पाई, सरकार चाहें जिस भी पार्टी की रही हो, कब्जा करने की घटनाएं कम नहीं हुई। कहा भी जाता है, कि बिना सत्ता पक्ष के ईशारे के कोई भी व्यक्ति एक इंच भी सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं कर सकता है। इसी तरह का एक मामला बनकटी ब्लॉक के दीवार के पीछे पीडब्लूडी की जमीन पर 'पवन चैहान' नामक व्यक्ति के द्वारा न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उस जमीन पर दो दुकान का अवैध निर्माण भी करवाया, यह यही पर नहीं रुके इन्होंने दोनों दुकानों को किराए पर उठा दिया, और यह अच्छा खासा किराया वसूल रहे है। अगर, यह खुद कोई

कारोबार करते तो लोगों को उतनी शिकायत नहीं होती, मगर, यह तो अपनी संपत्ति समझकर किराया लेने लगे।

बहरहाल, पीडब्लूडी इसे संज्ञान में लेकर इन्हें नोटिस देने जा रही है। क्षेत्र के लोगों का कहना है, कि अगर नगर पंचायत बनकटी प्रशासन सिर्फ अपनी ही जमीनों पर से कब्जा हटवा दे तो विकास के रास्ते खुल जाएगें। इसमें सबसे अधिक जमीनों पर कब्जा तो नगर पंचायत के गठन के पहले का हैं, यानि अधिकांश कब्जा ग्राम पंचायतों के कार्यकाल के दौरान प्रधानों और लेखपालों ने मिलकर किया/करवाया। आज उसी का बोझ नगर पंचायत बनकटी उठा रही हैं, नगर पंचायत को विरासत में जो सरकारी संपत्तियां मिली उस पर अधिकांश पर पहले से कब्जा था। अब सवाल उठ रहा है, कि जिन सरकारी जमीनों पर पक्के कई मंजिला इमारत खड़ा हो चुका है, उसे नगर पंचायत कैसे खाली करवाएगी, क्यों कि अब इन्हें तो नगर पंचायत को भी चलाना है, और सभासदों का हित भी देखना है।

क्यों कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनमें कई अब सभासद बन चुके हैं, और कई तो पूर्व भी हो चुके है। इसी लिए कहा जाता है, कि नगर पंचायत प्रषासन को अपनी जमीनों पर से कब्जा हटवाना आसान नहीं होगा, नगर पंचायत प्रशासन की उपलब्धि उसी में मानी जाएगी, कि अब कोई उनकी जमीनों पर कब्जा न पाए। इसके लिए नगर पंचायत प्रषासन को अपनी जमीनों पर कड़ी नजर रखनी होगी, और उन जमीनों पर नगर पंचायत बनकटी की संपत्ति को बोर्ड लगाना होगा।

सड़क हादसे में घायल किशोरी की इलाज के दौरान मौत

ऊंचाहार/रायबरेली : लखनऊ प्रयागराज राजमार्ग पर सड़क पार कर रही किशोरी को बाइक सवार ने एक दिन पहले टक्कर मारकर घायल कर दिया गया था। हादसे में घायल किशोरी की गुरुवार को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है ,सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह हादसा बुधवार को लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बाबा का पुरवा गांव के पास हुआ था। क्षेत्र के गांव केवलपुर मजरे इटौरा बुजुर्ग निवासी राजेंद्र प्रसाद की 17 वर्षीया पुत्री लवली सड़क पार कर रही थी, तभी राजमार्ग पर पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। जिससे किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आसपास के लोगों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर दशा को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। परिजन जिला मुख्यालय पर उसे एक निजी चिकित्सालय में ले गए। जहां पर किशोरी का इलाज हो रहा था। गुरुवार की दोपहर इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाई की जा रही है।

'दो सालों' में 300 'प्रोजे ट' को किया 'साकार' : यशकांत

पुरानी परिपाटी को तोड़ा, विकास पुस्तिका के जरिए दी गई योजनाओं की जानकारी

❖ ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत में 60-40 के अनुपात को पूरा कराने का किया प्रयास

❖ स्वच्छ भारत मिशन के तहत 52 ग्राम पंचायतों में हो रहा काम, मानकनुसार हो रहा आरसीसी सेंटर का निर्माण

❖ 2024-24 के लिए रामनगर में मनरेगा लेबर का 19.59 करोड़ हुआ पास

तेजयुग न्यूज़

बस्ती। क्षेत्र पंचायत रामनगर के बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह ने कहा कि यह ब्लॉक जिला का ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा ब्लॉक हैं, जो विकास पुस्तिका के जरिए क्षेत्र के लोगों को एक-एक विकास और उस पर खर्च होने वाले धन का ब्यौरा दिया। कहा कि हमने उस परिपाटी को तोड़ा जिसमें क्षेत्र और ग्राम पंचायतों के द्वारा करवाए गए विकास कार्यो की जानकारी नहीं दी जाती थी, हमने प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एसआईबी के जरिए गांव वालों को योजनाओं की जानकारी के साथ उसके लागत को भी बताया। बिना शिलापट्ट लगाए एक भी परियोजनाओं का उदघाटन होने नहीं दिया।

कहा कि हमने क्षेत्र के लोगों को विकास की जानकारी देने के उनके अधिकारों की रक्षा किया। क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के कार्यो में पारदर्शिता लाने का पूरा प्रयास किया, मनरेगा में 60-40 के अनुपात को मेनटेन करवाया। कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 52 ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है, मानकनुसार आरआरसी का निर्माण हो रहा है। डीएम के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जिसमें सभी ग्राम पंचायतों में मत्स्य पालन एवं केले की खेती के लिए महिलाओं को प्ररित किया। बताया कि मत्स्य पालन की रखवाली महिलाए करेंगी जिसमें प्रत्येक महिलाओं को इसके लिए छह हजार मानदेय मिलेगा, और यह मानदेय ग्राम पंचायतें देगी।

विकास खण्ड रामनगर के सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी व प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में पहले पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गई। बैठक में मनरेगा लेबर बजट का कुल 1959.58 लाख एवं 511221 मानव दिवस का बजट 2024-25 के लिए अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारिओं द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध मे जानकारी दी गयी। इस बैठक में खण्ड विकास अधिकारी सुश्री वर्षा वंग, सुहेल खान, लेखाकार अनिल कुमार, पशुचिकित्साधिकारी, बालविकास परियोजनाधिकारी एवं सचिव गण, प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य गण उपस्थित रहे।

'सीएमओ' ने 'खोली' बिना 'लाइसेंस' के 'भ्रष्टाचार' की 'दुकान'

जब तक 35 फीसद बखरा नहीं मिल जाता, तब तक टेंडर मिलने को कौन कहे भाग तक नहीं लेने दिया जाता

▸▸ जो भी ठेकेदार या व्यक्ति काम मांगने जाता, तो उससे पूछते कुछ लाए हो ▸▸ जिस ठेकेदार ने एडवांस में बखरा नहीं दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया ▸▸ अधिकर न होने के बाद भी सीएमओ बखरा मिल जाने के बाद सेम्पुल को रिजेक्ट कर देते ▸▸ हेल्थ वेलनेस सेंटर में सामानों की आपूर्ति और टेंडर के नाम पर सीएमओ की टीम ने किया बड़ा खेल ▸▸ इनके भ्रष्टाचार के दुकान की शिकायतें दो-तीन फर्मे और विधायक तक कर चुके ▸▸ हाथी का दांत साबित हो रहा जिला स्वास्थ्य समिति और टेंडर कमेटी ▸▸ सीएमओ कार्यालय में स्थापित इस भ्रष्टाचार के दुकान के खुलने का समय सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे तक हैं, आवास पर रात्रिकालीन सेवा भी उपलब्ध

तेजयुग न्यूज़

बस्ती।...सुनने में अजीब लग रहा होगा, मगर यह सच है, कि सीएमओ ने अपने कार्यालय और आवास पर बिना लाइसेंस के 'भ्रष्टाचार' की दुकान खोल रखी है। इस भ्रष्टाचार की दुकान में ठेका रुपी सामान पाने के लिए 35 फीसद का 80 फीसद रकम एडवांस में जमा करना पड़ता है। यानि अगर एक करोड़ का सामान/ठेका पाना है, तो 28 लाख रुपया एडवांस में जमा करना होगा, अवशेष सात लाख सामान पाने के बाद देना होगा। ध्यान रहे, 18 फीसद जीएसटी काटकर सामान नहीं मिलता बल्कि जीएसटी पर भी बखरा देना पड़ता है।

अगर, किसी ने बिना एडवासं जमा किए सामान खरीदने के लिए यानि ठेका पाने के लिए टेंडर डाल दिया तो उसके टेंडर को सेम्पुल का बहाना बना कर रिजेक्ट कर दिया जाता। सीएमओ कार्यालय में स्थापित इस भ्रष्टाचार के दुकान के खुलने का समय सुबह दस बजे से लेकर पांच बजे तक हैं, अगर कोई सामान पाने वचिंत रह जाता है, तो वह इनके आवास पर रात्रिकालीन सेवा के तहत एडवांस जमा करके सामान ले सकता है। यानि भ्रष्टाचार की दुकान कभी बंद नहीं होती। बस खरीदार होना चाहिए। ध्यान रहे, सामान तभी मिलेगा, जब आप एडवांस जमा करेंगें, क्यों कि इनके सामान की बहुत डिमांड है। लाइन लगाकर सामान बिकता है। इनके भ्रष्टाचार के दुकान की शिकायत दो फर्मे और एक विधायक कर चुके हैं, बावजूद बिना लाइसेंस के चलने वाले दुकान को बंद नहीं किया गया। वैसे इस दुकान के एक नहीं दो तीन पार्टनर हैं, जिसमें नामित जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सीटीओ और टेंडर कमेटी।

जिले के 273 हेल्थ वेलनेस सेंटर में आपूर्ति होने वाले थर्मामीटर, मलेरिया किट, वजन मशीन, कुर्सी और मेज के नाम पर सीएमओ कार्यालय में दुकान खुला है। खासबात यह है, कि सीएमओ की ओर से जो 35 फीसद बखरा लिया जाता है, उसमें कार्यालय या सामानों की प्राप्ति करने वाले को एक रुपया भी नहीं मिलता। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई अपना बखरा मांग सके। इसी लिए कोई सहयोग भी नहीं करता। कहने का मतलब यहां पर 'सिंगल विंडो सिस्टम' है। अब सवाल यह है, कि जब ठेकेदार 35 फीसद बखरा देगा तो वह कैसे गुणवत्तापरक सामानों की आपूर्ति करेगा। मगर, नहीं, ठेकेदार सामानों की आपूर्ति करे या न करें, या फिर वह गुणवत्ताविहीन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा सवाल यह है, कि जब सीएमओ को सेम्पुल रिजेक्ट करने का अधिकार ही नहीं है, तो यह कैसे निरस्त कर रहे हैं, और टेंडर कमेटी और जिला स्वास्थ्य समिति क्या कर रही है? यह भी सवाल उठ रहा है, कि आखिर किसके रिपोर्ट पर सेम्पुल को रिजेक्ट किया जा रहा है। सीधी सी बात है, कि जिसने सामान की अधिक कीमत दी, उसे सामान मिल गया, और जिसने कम दिया या फिर दिया ही नहीं तो उसे सामान रुपी ठेका नहीं मिला। बार-बार सवाल उठ रहा है, कि करोड़ों का घोटाला करने वाले आज तक किसी सीएमओ के खिलाफ स्थानीय प्रशासन स्तर पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और क्यों नहीं षासन को लिखा गया?

सीएमओ के खिलॉफ कार्रवाई न होने और घोटाला करने के बाद भी बच जाने के पीछे जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रुप में डीएम का हस्ताक्षर होना बताया जाता है। यह भी सही है, कि डीएम को हर चीज की जानकारी नहीं होती है, और सीएमओ हस्ताक्षर करवा लेते हैं, यह बात जिले के प्रभारी मंत्री ने भी मीडिया के सवाल के जबाव में कहा था। यह मामला प्रेसवार्ता के जरिए जिले के प्रभारी मंत्री के सामने भी उठा था, कि डीएम के हस्ताक्षर होने से कोई जांच कमेटी कार्रवाई ही नहीं करती। चाहें सीएमओ हो या फिर एसआईसी या फिर सीएमएस इस लिए बचते रहे हैं, क्यों कि डीएम की चिढ़िया बैठती रही।

शिकायत करने वाले अनेक ठेकेदारों का कहना है, कि वह लोग डीएम से शिकायत करत-करते रह जाते हैं, जांच कमेटी तो बना दी जाती हैं, दिखाने के लिए बयान भी ले लिए जाते हैं, लेकिन सालों बीत जातें है, जांच पूरा नहीं होता, और जब तक जांच पूरी नहीं होगी, तब तक कार्रवाई भी नहीं होगी। जिस तरह सीएमओ कार्यालय में जेम पोर्टल का सहारा लेकर लूटपाट मचा है, उसे देखकर ही कहा जा रहा है, कि सीएमओ साहब ने अपने कार्यालय और आवास पर भ्रष्टाचार की दुकान बिना लाइसेंस की खोल रखी है।

'डीएम' ने 'सचिव' को दिया 'रेडक्रॉस' का 'दानपात्र'

इसी दानपात्र में घूम-घूमकर दान लिया जाएगा, पहला दान डीएम ने दिया

❖ इसी दान से आपात काल में जरुरतमंदों, असयहाय, निरीह, विधवा और बुजुर्ग की जरुरतों को पूरा किया जाएगा

तेजयुग न्यूज़

बस्ती। रेडक्रास सोसायटी लखनउ उ.प्र. की ओर से जरुरतमंदों की जरुरतों को पूरा करने के लिए एक नई पहल शुरू किया है। इसके तहत रेडक्रास सोसायटी ने सभी जनपदों को एक दानपात्र उपलब्ध कराया है, और कहा है, कि इसी दानपात्र में दान देने के इच्छुक दानवीरों से दान लिया जाए। सोसायटी के सचिव सरदार कुलवेंद्र सिंह ने बताया कि, सोसायटी के अध्यक्ष डीएम अन्द्रा वामसी ने सीलबंद दानपात्र सौंपा।

दान देने की शुरुआत डीएम ने दान देकर की। बताया कि दानपात्र से जरुरतमंदों, असयहाय, निरीह, विधवा और बुजुर्ग की जरुरतों को पूरा किया जाएगा बताया कि अगर कोई चेक के जरिए दान देना चाहता है, तो सोसायटी के नाम से दे सकते है। बताया कि बारकोड के जरिए मोबाइल से भी दान देने के प्रयास किए जा रहे है। ताकि अधिक से अधिक दान मिल सके। क्यों कि आजकल अधिकांश लोग मोबाइल के जरिए लेन-देन करते है। इस दौरान कार्यक्रम में काजी फरजान, कुलदीप सिंह, अब्दुल हलीम, लाडले हैदर रिजवी, सिद्धांत मिश्रा, रशिम अग्रवाल, सरदार दिपेंद्र सिंह एडवोकेट व आयूष सिंह मौजूद थे। ऐस्प्रा ज्वेल्स की स्वामिनी, संचालिका स्कूल ने दान कर सदस्यों का हौसला अफजाई किया।

'पालिका' कार्यालय पर '18' से 'धरने' पर बैठेगें 'पेंशनर्स'

तेजयुग न्यूज़

बस्ती। समस्याओं और मांगों को लेकर पालिका कार्यालय पर पेंशनर्स की बैठक हुई। जिसमें यह निर्णय हुआ किवह 18 मार्च से पालिका कार्यालय अनिश्चित कालीन धरने पर बैठेगें। जिन मांगों को लेकर धरने पर बैठने का निर्णय हुआ, उनमें माह के अतिंम दिन पेंशन भेजने, वास्तविकता से कम पर निर्धारित पेंशन को सही करने, पात्र कर्मचारियों का पेंशन पदोन्नति वेतनमान निर्धारित करने, पीएफ बकाया, ऋण कटौती, महगांई भत्ता, बोनस, एरियर का भुगतान करना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल एक सप्ताह में प्रस्तुत करने, बकाया एवं भुगतान विवरण उपलब्ध कराने, कार्यालय में प्रार्थना पत्र लंबित न रखने और हाईकोर्ट जाने वाले कर्मचारियों को वाद व्यय, वकील खर्च देना षामिल है। बैठक में सत्यदेव षुक्ल, विनोद अग्रहरि, अब्दुल सत्तार, बाबूराम, सर्वजीत चौधरी, रामनरायन चैधरी, ओमप्रकाश पांडेय, बजरंगबली और अनिल कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे।